

देशभर की खुफिया एजेंसियों से सीधे जुड़ेगा कानपुर, एक क्लिक पर मलिंगा बड़े अपराधियों का डाटा

चर्चा में क्यों?

13 जुलाई, 2023 को मीडिया से मली जानकारी के अनुसार अपराधियों पर लगाम और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को जल्द मैक (मल्टी एजेंसी सेंटर) से जोड़ दिया जाएगा, जिससे देश के किसी भी अपराधी की तस्वीर व उसकी पूरी जानकारी एक क्लिक पर हासिल हो जाएगी।

प्रमुख बद्दि

- कानपुर शहर को मैक (मल्टी एजेंसी सेंटर) से जोड़ने से आईबी, एनआईए, राॅ, एटीएस जैसी तमाम इंटेलीजेंस एजेंसियाँ सीधे इस शहर से इनपुट साझा कर सकेंगी।
- वदिति है कि पहले यह ससि्टम सरिफ राज्ज मुख्वालयाँ तक ही सीमति था, अब शहरों में भी इन्हें स्थापति कथिा जाएगा इसलथि इसे एसमैक (सब्सडिरी मल्टी एजेंसी सेंटर) कहा जाएगा। कानपुर के अलावा प्रदेश के 78 शहरों को इसमें शामिल कथिा गया है।
- मैक को क्राइम ब्रांच में इंस्टाल कथिा जाएगा। जो ससि्टम क्राइम ब्रांच में लगेगा, उसमें एक इंटरनेट लाइन होगी, जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसे संबंथति व्क्ती ही अपनी लॉगइन आईडी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। इसे इंटरनेट की तरह हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता।
- इससे एक हाई सक्रियोरड टेलीफोन लाइन जुड़ी होगी जसि हॉट लाइन भी कहते हैं। हर खुफिया एजेंसी से एक अफसर (वन प्वाइंट कॉन्टेक्ट) इस ससि्टम को हैंडल करेगा।
- इससे आतंकी गतविधियाँ, बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ, सोना और नकली नोटों की तस्करी जैसे बड़े अपराधों की सूचना पुलसि को एक कॉल पर उनके ससि्टम पर उपलब्ध होगी। कानपुर में बैठे पुलसि अफसर पता लगा सकेंगे कथिां का रहने वाला अपराधी देश के कनि-कनि शहरों में कथा-कथा अपराध कर चुका है। इसी तरह दूसरे शहर से आए अपराधियों की भी जानकारी आसानी से हो जाएगी। यह इनपुट यहाँ की पुलसि चंद सेकेंड में पूरे देश को दे सकेंगी।
- गौरतलब है कि 3 मई, 1999 से 26 जुलाई, 1999 के बीच कारगलि युद्ध के बाद मैक की स्थापना हुई। इसकी नोडल एजेंसी आईबी को बनाया गया था।
- ज्जातव् है कि अब तक मैक सरिफ राज्जों को दथिा गया था। इसमें उत्तर प्रदेश में इसका ससि्टम एसटीएफ के पास था। हालाँकि बाद में एक ससि्टम एटीएस में भी इंस्टाल कथिा गया था।
- इस ससि्टम को लगाने का मुख् उद्देश्ज साइबर स्पेस के अवैध इस्तेमाल, क्राइम टेरर नेक्सस, नार्को-टेररजि्म, टेरर फाइनेंसिगि, ग्लोबल टेरर गुरुप्स, वदिशी आतंकवादियों की आवाजाही की जानकारियाँ हासलि कर एजेंसियों से साझा करना है। इसे यूएन (यूनाइटेड नेशन) की सीआईसी (सेंटरल इंटेलीजेंस एजेंसी) के आधार पर बनाया गया है।